



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2001/अग्रहायण 7, 1923

No. 314]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2001/AGRAHAYANA 7, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2001

सं. टीएमपी/8/2000-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार प्रयोक्ताओं/पत्तन न्यासों द्वारा की गई विलंबित अदायगियों/वापसियों पर लगाए जाने योग्य दंडात्मक ब्याज की दर में कमी के लिए भारतीय पत्तन संघ के प्रस्ताव का निपटान करता है और यहां इसके साथ संलग्न आदेशानुसार सभी महापत्तनों द्वारा साझा तौर पर अपनाए जाने के लिए दंडात्मक ब्याज की संशोधित सीमा निर्धारित करता है।

अनुसूची

(मामला सं० टीएमपी/8/2000-सामान्य)

भारतीय पत्तन संघ (आईपीए)

.....

आवेदक

आदेश

(नवम्बर, 2001 के 5वें दिन पारित किया गया)

यह मामला भारतीय पत्तन संघ द्वारा प्रयोक्ताओं/पत्तन न्यासों द्वारा विलंबित अदायगियों/वापसियों पर दंडात्मक ब्याज की दर में कमी करने के लिए अनुरोध करते हुए भेजे गए एक प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. अपने प्रस्ताव में आईपीए ने निम्नलिखित बिंदुओं का वर्णन किया है :-

- (i) प्राधिकरण द्वारा अपने दिनांक 23 फरवरी, 2000 के आदेश सं० टीएमपी/8/2000-सामान्य में अनुमोदित विलंबित अदायगियों/वापसियों के लिए दंडात्मक ब्याज अलग-अलग पत्तनों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अधिसूचित प्रतिवर्ष दर के न्यूनतम और 1% जोड़कर तथा 15% अधिकतम के बीच की सीमा में नियत किए जाएं।
- (ii) वापसी में विलम्ब की गिनती प्राधिकरण के आदेश में यथाउल्लिखित 20 दिनों की बजाय सेवा पूरी होने की तारीख से 30 दिनों के बाद ही की जाए।

3.1. फरवरी, 1998 में चेन्नई में आयोजित कार्यशाला में अपनाया गया एक दिशानिर्देश इस आशय का था कि पत्तन न्यास विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज अदा करेंगे। अपनाए गए दिशानिर्देश के आधार पर इस प्राधिकरण ने सभी महापत्तन न्यासों द्वारा समरूप अपनाए जाने के लिए दिनांक 4 फरवरी, 2000 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 23 फरवरी, 2000 को अधिसूचित किया गया था।

3.2. उक्त आदेश में प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्णय लिया था :—

- (i) प्रयोक्ता विलंबित भुगतानों पर प्रतिवर्ष 24% की दर पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा।
- (ii) इसी प्रकार, पत्तन न्यास विलंबित वापसियों पर प्रतिवर्ष 24% की दर पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा।
- (iii) वापसियों में विलंब की गिनती सेवा पूरी होने की तारीख से केवल 20 दिनों अथवा प्रयोक्ता से अपेक्षित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, इनमें से जो भी बाद में हो, से की जाएगी।

4.1. इस आदेश के प्रत्युत्तर में, विभिन्न पत्तन न्यासों ने निर्धारित ब्याज दरों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। इन पत्तनों तथा अन्य पत्तनों को भी इस विषय पर एक समरूप ब्याज दर, जिसे पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा की गई विलंबित अदायगियों और पत्तन न्यासों द्वारा किए गए विलंबित भुगतानों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, अपनाने के लिए सभी महापत्तन न्यास के समन्वित दृष्टिकोण के लिए आईपीए के मंच पर चर्चा करने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार, आईपीए ने मामले पर चर्चा की और अपना विचार सूचित किया कि प्रत्येक पत्तन को अपनी नीति का निर्णय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

4.2. इस मामले पर इस प्राधिकरण द्वारा आईपीए द्वारा दी गई राय और कुछ पत्तन न्यासों द्वारा भेजे विचारों की पृष्ठभूमि में दिनांक 16 मई, 2001 को हुई अपनी बैठक में पुनः विचार किया गया था और निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे:—

- (i) महापत्तन न्यासों के दरों के मान में विलंबित अदायगी/वापसी के लिए दंडात्मक ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण की दक्षता के बारे में उठाए गए प्रश्न को इस प्राधिकरण द्वारा अपने दिनांक 19 जूलाई, 2000 के आदेश के माध्यम से पहले ही निपटाया जा चुका था।
- (ii) इस प्राधिकरण के दिनांक 4 फरवरी, 2000 के आदेश के पीछे आशय दोनों तरफ से अर्थात् पत्तन प्रयोक्ताओं तथा साथ ही पत्तन न्यास द्वारा विलंबित भुगतान पर देय दंडात्मक ब्याज की एकरूपता निर्धारित करना था। आदेश में, इस प्राधिकरण ने विलंबित भुगतानों के लिए आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए प्रभारित किए जा रहे दंडात्मक ब्याज पर विचार करते हुए ऐसे मामलों के लिए 24% ब्याज निर्धारित किया। यह प्राधिकरण निर्णय ले चुका था कि अगर आदेश के पीछे आशय को उसकी सही भावना के अनुरूप समझा गया था तो यह प्राधिकरण समय-सीमा अथवा दंडात्मक ब्याज की दर के बारे में चिंतित नहीं था। ब्याज की दर चाहे कुछ भी थी, ऐसा निर्धारण दोनों पक्षों पर समरूप तौर पर लागू होगा।
- (iii) यहां तक कि यद्यपि इस प्राधिकरण की वर्णित स्थिति यह रही है कि यह दंडात्मक ब्याज की दर के बारे में चिंतित नहीं है, फिर भी ऐसी दरों का निर्णय करना प्रत्येक पत्तन न्यास पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस संबंध में सभी महापत्तन न्यासों के बीच समरूपता होनी होगी। केवल इसी विचार पर ही, इस प्राधिकरण ने समरूप ब्याज दर अपनाने के लिए सभी महापत्तन न्यासों के समन्वित विचार के लिए इस मामले पर पत्तनों को आईपीए के मंच पर चर्चा करने का सुझाव देने का निर्णय लिया था। उस समय आईपीए द्वारा दिए गए उत्तर में उसे भेजे मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। कानूनी रूप से, प्रत्येक पत्तन को प्रशुल्क मामलों से संबंधित अपनी नीति का निर्णय करने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। चूंकि, आईपीए समरूप ब्याज दर पर कोई समन्वित दृष्टिकोण की सिफारिश नहीं कर पाया, इसलिए इस प्राधिकरण ने बैंकों और आयकर विभाग द्वारा वाणिज्यिक दरों में कमी के संदर्भ में दंडात्मक ब्याज की दर पर स्वप्रेरणा से निर्णय लिया।

4.3. सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने के बाद इस प्राधिकरण ने दिनांक 4 फरवरी, 2000 के अपने आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए दिनांक 16 मई, 2001 को एक आदेश निम्नानुसार पारित किया :—

- (i) प्रयोक्ता विलंबित भुगतानों पर प्रति वर्ष 18% की दर पर दंडात्मक ब्याज अदा करेंगे।
- (ii) इसी प्रकार, पत्तन न्यास विलंबित वापसियों पर प्रतिवर्ष 18% की दर पर दंडात्मक ब्याज अदा करेंगे।

5. मुरुगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) ने पत्तन प्रयोक्ताओं को बिल की प्राप्ति की तारीख से छूट की अवधि के रूप में 7 स्पष्ट कार्यदिवस प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एमओपीटी के प्रस्ताव पर इस संबंध में समरूप निर्धारण को अपनाने के लिए सभी अन्य महापत्तनों के साथ परामर्श के बाद विचार किया गया था। दिनांक 4 फरवरी, 2000 के पूर्व आदेश को संशोधित (दिनांक 16 मई, 2001 के आदेश द्वारा अंशतः संशोधित) करते हुए दिनांक 30 अगस्त, 2001 को एक आदेश पारित किया गया था। इस प्राधिकरण ने दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अपने आदेश में निम्नलिखित अनुमोदित किया :-

“प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान में विलंब पत्तन न्यासों द्वारा बिल देने की तारीख के केवल 10 दिनों बाद गिना जाएगा। तथापि, यह उपबंध उन मामलों, जहां भुगतान महापत्तन न्यास अधिनियम में यथा निर्दिष्ट पत्तन न्यास की संपत्तियों के प्रयोग/सेवाओं को प्राप्त करने के पूर्व किया जाना है और/अथवा दरों के मान में शर्त के रूप में अग्रिम तौर पर प्रभागों का भुगतान निर्धारित किया जाता है, पर लागू नहीं होगा।

6. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) ने दंडात्मक ब्याज की दर घटाकर 12.5% करने का और पत्तन न्यासों को बीजक तैयार करने की तारीख से 10 दिनों की छूट अवधि पर विचार करने का भी अनुरोध करते हुए अब एक पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अपने प्रस्ताव में जेएनपीटी ने निम्नलिखित मुद्दों का वर्णन किया है :-

- (i) पूर्व में विलंबित भुगतानों और वापसियों पर कोई दंडात्मक ब्याज प्रभार्य नहीं था।
- (ii) इसलिए, पत्तन प्रयोक्ता विलंबित भुगतानों/वापसियों पर दंडात्मक ब्याज प्रभारित करने से संबंधित आदेश कार्यान्वित नहीं करने का अनुरोध कर रहे हैं और यह कहा है कि 18% ब्याज की दर अधिक है।
- (iii) जेएनपीटी प्रयोक्ताओं के विचारों से भी सहमत है और उसके न्यासी बोर्ड ने ऐसे दर जो भारतीय स्टेट बैंक की मूल ऋणदाय दर, जो इस समय 11.5% है, की अपेक्षा 1% अधिक है, तक ब्याज कम करने के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से अनुरोध करने का निर्णय किया है। इसलिए, जेएनपीटी ने विलंबित भुगतान/वापसी पर 12.5% ब्याज का प्रस्ताव किया है।
- (iv) जेएनपीटी ने भुगतान करने के लिए पत्तन प्रयोक्ताओं को बीजक की तारीख से 10 दिनों की छूट अवधि की अनुमति देने की भी सिफारिश की है।

आईपीए और जेएनपीटी द्वारा अब किए गए प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

- (i) पहले, इस प्राधिकरण ने सभी पत्तन न्यासों को इस मामले पर समरूप ब्याज दर अपनाने और उस सीमा, जिसके बाद दंडात्मक उपबंध लागू होंगे, के बारे में भी एक समन्वित दृष्टिकोण बनाने के लिए आईपीए के मंच पर चर्चा करने का सुझाव दिया था। इसके प्रत्युत्तर में, आईपीए ने तब अपना विचार सूचित किया था कि प्रत्येक पत्तन को अपनी नीति का निर्णय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चूंकि, आईपीए द्वारा दिए गए उत्तर ने उसे भेजे मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया और प्रत्येक पत्तन को कानूनी तौर पर अपनी प्रशुल्क नीति पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, इसलिए इस प्राधिकरण ने दंडात्मक ब्याज की दर पर निर्णय लेने के लिए स्वप्रेरणा से कार्यवाही की और उसे प्रतिवर्ष 24% से घटाकर प्रतिवर्ष 18% किया।

अब आईपीए ने दंडात्मक ब्याज की दर पर एक विशेष सुझाव दिया है। आईपीए का प्रस्ताव ब्याज दर की एक सीमा निर्धारित करना और प्रत्येक पत्तन न्यास को निर्धारित सीमा के भीतर ब्याज दर चुनने की अनुमति देने का है।

- (ii) यह मानना होगा कि इस प्राधिकरण के आदेश का आशय दोनों तरफ से देय दंडात्मक ब्याज की समरूपता निर्धारित करना है। विचार केवल समान अवसर प्रदान करने के सिद्धांत पर बल देना है। यह प्राधिकरण यह दृष्टिकोण ले चुका है कि अगर आदेश के आशय को उसके सच्चे अर्थों में सही रूप से समझा जाता है, तो यह समय सीमा अथवा दंडात्मक ब्याज दर के बारे में चिंतित नहीं है। यहां तक कि यद्यपि, दंडात्मक ब्याज की दर अधिक महत्व नहीं रखती, फिर भी इस प्राधिकरण की यह राय थी कि इसे प्रत्येक पत्तन न्यास पर निर्णय करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता और इस संबंध में सभी महापत्तनों के बीच समरूपता होनी चाहिए। इस परिदृश्य में देखे जाने पर पत्तन न्यासों को नियत की जाने वाली सीमा से अपनी पसंद की

ब्याज दर का चयन करने के लिए स्वतंत्रता की अनुमति देने का आईपीए का प्रस्ताव महापत्तनो पर प्रशुल्क नियतन के मामले में समरूप सिद्धांत और सकल्पना अपनाने के इस प्राधिकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं हो सकता ।

इस परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर इस प्राधिकरण की सोच के अर्थ और विषयवस्तु को सारांश में प्रस्तुत करना उपयोगी हो सकता है —

(क) दंडात्मक दर चाहे कुछ भी हो, वह पत्तन न्यासों और पत्तन प्रयोक्ताओं दोनों के लिए समान होगी ।

(ख) दर चाहे कुछ भी हो, वह सभी पत्तन न्यासों के लिए समान होगी ।

पत्तन न्यासों ने इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक इस मामले में इस प्राधिकरण के हस्तक्षेप को स्वीकार किया है और उसने समानता के विचार से दोनों तरफ समान दर होने की आवश्यकता भी स्वीकार की है । परंतु, भिन्न-भिन्न वित्तीय विशेषताओं से हुई स्थानीय विशिष्टताओं के कारण वे एक साझा दर के बारे में सहमति पर नहीं पहुंच पाए । इस मूल वास्तविकता को मानते हुए, यह प्राधिकरण अपने पूर्व निर्णय से अलग होने और अपने आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के संवर्धन के लिए व्यवस्था में कुछ लचीलापन लाने का इच्छुक है ।

(iii) सदिग्ध ऋणों पर दंडात्मक ब्याज जोड़ने से उत्पन्न अवास्तविक स्थिति भी विचारार्थ एक सगत मुद्दा है । तथापि, विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज लगाना एक सुव्यवस्थित वाणिज्यिक व्यवहार है । कुछ ऋणों के डुबत और सदिग्ध होने से ही ऐसे स्थापित व्यवहार को छोड़ देने का कोई कारण नहीं है ।

(iv) आईपीए ने दंडात्मक ब्याज की दर 15% से घटाने और उसे उच्चतम सीमा के रूप में नियत करने का प्रस्ताव किया है । यह उल्लेखनीय है कि दंडात्मक ब्याज दर को हाल ही में 24% से घटाकर प्रतिवर्ष 18% किया गया है । चूंकि, दंडात्मक ब्याज दर की एक सीमा निर्धारित की जानी है, इसलिए पहले से लागू दंडात्मक ब्याज दर, जो संबोधित निर्धारण में केवल एक उच्चतम सीमा का कार्य करेगी, को कम करने की आवश्यकता नहीं होगी । यह मानना होगा कि पत्तन न्यासों को सीमा के भीतर दंडात्मक ब्याज दर अपनाने की नम्यता होगी और यह प्रतिवर्ष 18% से कम हो सकती है ।

(v) दंडात्मक ब्याज को एक अनुशासित नकदी और ऋण प्रबंध लागू करने के लिए एक दंडात्मक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए । इसे केवल रूकी निधियों की आवश्यकता लागत के रूप में देखना सही नहीं हो सकता । इस पृष्ठभूमि में आईपीए द्वारा यथाप्रस्तावित भारतीय स्टेट बैंक के मूल नकदी अनुपात से 1% अधिक पर दंडात्मक ब्याज दर निर्धारित करने से वांछित परिणाम प्राप्त करना प्रतीत नहीं होता । यह मानना होगा कि बिरले ही कोई उधारकर्ता मूल नकदी अनुपात (पीएलआर) पर ऋण प्राप्त कर सकता है । इसके अतिरिक्त, अगर दंडात्मक ब्याज दर वाणिज्यिक उधार लेने की दर के समीप है तो (लेन-देन करने वाली अन्य पार्टों द्वारा) पत्तन न्यासों/प्रयोक्ताओं को एक निक्षेपागार अथवा ऋणदाय एजेंसी के रूप में देखने की प्रवृत्ति हो सकती है । इसे ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण भारतीय स्टेट बैंक के मूल नकदी अनुपात (पीएलआर) दर से न्यूनतम 2% अधिक और प्रतिवर्ष 18% अधिकतम के बीच सीमा के भीतर दंडात्मक ब्याज दर निर्धारित करना उचित समझता है । पत्तन न्यासों को निम्नलिखित बातों के अधीन इस सीमा के भीतर अपने प्रयोजन के लिए सुविधाजनक दर को चुनने की अनुमति दी जा सकती है —

(क) चुनी गई दंडात्मक ब्याज दर पत्तन न्यासों और पत्तन प्रयोक्ताओं, दोनों पर समान रूप से लागू होगी ।

(ख) पत्तन न्यासों को अपने विकल्प का प्रयोग करना और निर्धारित सीमा के भीतर दर चुनना चाहिए । उसके बाद कोई भी परिवर्तन इस प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जा सकता है ।

(ग) सीमा लागू करने से संबंधित व्यवस्था की यह जांच करने के लिए कि क्या सभी पत्तन न्यासों के लिए एक साझा दर निर्धारित की जा सकती है या नहीं, दो वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी ।

(vi) आईपीए ने भी प्रस्ताव किया है कि वापसी में विलंब की गिनती की समय-सीमा सेवा के 30 दिनों के पूरा होने की तारीख से 30 दिनों तक बढ़ा दी जाए । यह प्राधिकरण वापसी के ऐसे दावों पर कार्यवाही करने के लिए 20 दिनों की समय-सीमा की अनुमति दे चुका है । अनुमति दी जा चुकी समय-सीमा उदार है, शीर्ष समय में किसी और वृद्धि की आवश्यकता नहीं है । यह भी सगत है कि आईपीए का प्रस्ताव सेवाएं पूरी

होने की तारीख से शीर्ष समय पर विचार करने के लिए है । वापसी संबंधी दावों पर किसी पत्तन को कार्यवाही करने के लिए सेवाएं पूरी होना प्रयोक्ताओं द्वारा सभी परिप्रेक्ष्य में यह प्राधिकरण निर्धारित कर चुका है कि वापसी में विलंब की गिनती सेवाएं पूरी होने की तारीख अथवा प्रयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति पर, इनमें से जो भी बाद में हो, से केवल 20 दिनों से की जाएगी ।

- (vii) जेएनपीटी ने पत्तन प्रयोक्ताओं के लिए भुगतान करने हेतु बीजक की तारीख से 10 दिनों की छूट अवधि की अनुमति देने का सुझाव दिया है । यह प्राधिकरण अपने दिनांक 3 अगस्त, 2001 के आदेश द्वारा ऐसी छूट अवधि की अनुमति दे चुका है ।
- (viii) इस परिप्रेक्ष्य में, यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) और वेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) ने (बारम्बार) विलंबित भुगतान/वापसी के लिए दंडात्मक ब्याज दर निर्धारित करने के लिए इस प्राधिकरण की सक्षमता के बारे में संदेह उठाया है । यह मुद्दा इस प्राधिकरण द्वारा सीपीटी के संबंध में उसके दिनांक 19 जुलाई, 2000 के आदेश द्वारा निपटाया जा चुका है और सीएचपीटी के मामले में दोहराया गया है । सीपीटी से संबंधित आदेश में निम्नलिखित स्थिति का स्पष्टतः वर्णन किया गया था :-
 - (क) इस प्राधिकरण द्वारा दंडात्मक ब्याज के निर्धारण ने महापत्तन न्यास अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया ।
 - (ख) दरें और संबद्ध शर्तें निर्धारित करने के लिए अधिकार प्राप्त कोई प्राधिकरण दंडात्मक दरें भी निर्धारित कर सकता है ।
 - (ग) अगर सीपीटी द्वारा लगाया गया (यहां तक कि इस प्राधिकरण ने साझा अभिग्रहण आदेश पारित किया हो, के पूर्व अपने दरों के मान के अनुसार) दंडात्मक ब्याज युक्तिसंगत था, तब इस प्राधिकरण द्वारा पत्तन द्वारा की गई वापसियों पर सिद्धांत लागू करना भी उचित था ।

8.1 परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों तथा समग्र रूप से ध्यान दिए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित निर्णय लेता है :-

- (i) इस विषय पर अपने पूर्व आदेश के आंशिक संशोधन में दंडात्मक ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की मूल ऋणदाय दर से न्यूनतम 2% अधिक और अधिकतम 18% के बीच की सीमा में होगी, जिसके भीतर पत्तन न्यास अपने प्रयोजन की सुविधानुसार दर का चुनाव कर सकते हैं ।
- (ii) चुनी गई दंडात्मक ब्याज दर पत्तन न्यासों और पत्तन प्रयोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगी ।
- (iii) पत्तन न्यासों को तत्काल अपने विकल्प का प्रयोग करना और निर्धारित सीमा के भीतर किसी दर का चुनाव करना चाहिए । उसके बाद कोई भी परिवर्तन केवल इस प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जा सकता है ।
- (iv) किसी सीमा को लागू करने से संबंधित व्यवस्था की यह जांच करने के लिए कि क्या सभी पत्तन न्यासों के लिए साझा दर निर्धारित की जा सकती है, दो वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी ।

8.2. सभी महापत्तन न्यासों को उनके द्वारा (चुनी जाने वाली) दंडात्मक ब्याज की दर शामिल करने के लिए अपने संबंधित दरों का मान संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है ।

8.3 यह आदेश भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति पर लागू होगा ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2001/असाधा.]

3674 GA/2001-2

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2001

No. TAMP/8/2000-Genl.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of a proposal of the Indian Ports Association for a reduction in the rate of penal interest leviable on delayed payments/refunds made by users/port trusts and prescribes a revised range of penal interest rates for common adoption by all the major port trusts as in the Order appended hereto.

SCHEDULE**No. TAMP/8/2000-Genl.**

The Indian Ports Association (IPA)

— — —

Applicant

ORDER

(Passed on this 5th day of November 2001)

This case relates to a proposal sent by the Indian Ports Association (IPA) requesting for a reduction in the rate of penal interest on delayed payments / refunds by users / Port Trusts.

2. In its proposal, the IPA has made the following points:

- (i). The penal interest for delayed payment / refunds approved by the Authority in its Order No. TAMP/8/2000-Genl dated 23 February 2000 may be fixed by individual Ports within a range between a minimum of the State Bank of India notified rate plus 1% and a maximum of 15% per annum.
- (ii). Delays in refund may be counted only after 30 days from the date of completion of the services instead of 20 days as mentioned in the Order of Authority.

3.1. One of the Guidelines adopted at the Workshop held in Chennai in February 1998 was to the effect that the Port Trusts shall pay penal interest on delayed refunds. Based on the guideline adopted, this Authority passed an Order on 4 February 2000 for uniform adoption by all the Major Port Trusts. This Order was notified in the Gazette of India on 23 February 2000.

3.2. In the said Order, the Authority decided the following:

- (i). The user shall pay penal interest @ 24% per annum on delayed payments.
- (ii). Likewise, the Port Trust shall pay penal interest @ 24% per annum on delayed refunds.
- (iii). The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the user, whichever is later.

4.1. In response to this Order, various port trusts had submitted representations against the interest rate prescribed. These ports and also the other ports were advised to discuss the subject in the forum of the IPA for a coordinated view of all the Major Port Trust to adopt a uniform interest rate which

should be applied equally on delayed payments made by the port-users and delayed refunds made by the Port Trusts. The IPA accordingly, discussed the matter and conveyed its views that each port should have the freedom to decide its policy.

4.2. The matter was again considered by this Authority in its meeting held on 16 May 2001 in the backdrop of the opinion given by the IPA and the views sent by some of the Port Trusts and the following observations were made:

- (i). The question about the competence of the Authority to prescribe penal interest rate for delayed payment / refund in the Scale of Rates of Major Port Trusts had already been settled by this Authority through its Order dated 19 July 2000.
- (ii). The intention behind this Authority's Order dated 4 February 2000 was to prescribe a uniformity of penal interest payable on delayed payments both ways i.e., by port users as well as by the Port Trust. In the Order, this Authority prescribed a 24% interest for such cases taking into consideration the penal interest being charged for the year 1999-2000 by the Income Tax Department for delayed payments. This Authority had already taken a decision that if the intention behind the Order was correctly understood in its true spirit, this Authority was not concerned about the time limit or the penal interest rate. Whatever was the rate of interest such prescription would be uniformly applied to both sides.
- (iii). Even though the stated position of this Authority has been that it is not concerned about the rate of penal interest, it can not be left to the individual Port Trust to decide such rates. There has to be uniformity among all major Port Trusts in this regard. On this consideration only, this Authority had decided to advise the ports to discuss the matter in the forum of IPA for a coordinated view of all the major Port Trusts to adopt a uniform interest rate. The reply then given by the IPA did not address the issue referred to it. Legally, each port can not have freedom to decide its policy relating to tariff matters. Since the IPA failed to recommend any coordinated view on a uniform interest rate, this Authority *suo motu* decided on the rate of the penal interest with reference to reduction in commercial rates by banks and the Income Tax Department.

4.3. After considering all the issues involved, this Authority passed an Order on 16 May 2001 partially amending its Order dated 4 February 2000 as follows:

- (i). The user shall pay penal interest @ 18% p.a. on delayed payments.
- (ii). Likewise, the Port Trust shall pay penal interest @ 18% p.a. on delayed refunds.

5. The Mormugao Port Trust (MOPT) submitted a proposal to grant 7 clear working days as grace period from the date of the receipt of the bill to the port users. The proposal of the MOPT was considered after consultation with all other Major Ports for adoption of a uniform prescription in this regard. An Order was passed on 30 August 2001 amending the earlier Order dated 4 February 2000 (partially amended by Order dated 16 May 2001). This Authority in its Order dated 30 August 2001 approved the following:

“ The delay in payments by users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the Port Trusts. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services / use of Port Trust's properties as stipulated in the MPT Act and/or where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the Scale of Rates.”

6. The Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) has now submitted a separate proposal requesting to reduce the rate of penal interest to 12.5% and also to consider 10 days grace period from the date of preparation of invoices to the port users. In its proposal, the JNPT has made the following points:

- (i). In the past, no penal interest was charged on delayed payments and on refunds.
- (ii). The port users, therefore, are requesting for not implementing the Order relating to charging penal interest on delayed payment/refunds and also stated that 18% interest is on the higher side.

- (iii). The JNPT also agrees the views of the users and its Board of Trustees have decided to approach the TAMP to reduce interest at a rate that is 1% higher than that of SBI's prime lending rate which is at present 11.5%. The JNPT, has, therefore proposed 12.5% interest on delayed payment / refunds.
- (iv). The JNPT has also recommended allowing 10 days grace period from the date of the invoice to the port users for effecting the payment.

7. With reference to the proposals now made by the IPA and the JNPT, the following position emerges:

- (i). Earlier, this Authority advised all the port trusts to discuss the matter in the forum of the IPA to formulate a coordinated view about adoption of uniform penal interest rate, as also the time limit beyond which the penal provisions will apply. In response, the IPA then conveyed its view that each port should have the freedom to decide its policy. Since the reply given by the IPA did not address the issue referred to it, and each port could not legally have freedom to decide its tariff policy, this Authority proceeded *suo motu* to decide on the rate of penal interest and reduced it from 24% p.a. to 18% p.a.

Now the IPA has come up with a specific suggestion on the rate of penal interest. The proposal of the IPA is to prescribe a range of interest rates and allow individual port trusts to choose the interest rate within the range prescribed.

- (ii). It is to be recognised that the intention behind the Order of this Authority is to prescribe a uniformity of penal interest payable both ways. The idea is only to emphasise the principle of level playing field. This Authority has already taken a view that if the intention behind the Order is correctly understood in true spirit, it is not concerned about the time limit or the penal interest rate. Even though the rate of penal interest does not matter much, it was the opinion of this Authority that it could not be left to an individual Port Trust to decide; and, there must be a uniformity among all major port trusts in this regard. Viewed in this perspective, the proposal of the IPA to allow freedom to the port trusts to select the interest rate of their choice from the range to be fixed may not be in line with this Authority's approach to adopt uniform principles and concepts in the matter of tariff fixation at the major ports.

It may be useful in this context to recapitulate the pith and substance of this Authority's thinking on this subject:

- (a). Whatever may be the penal rate, it shall be the same for both the port trusts and the port-users.
- (b). Whatever may be the rate, it shall be the same at all the port trusts.

The port trusts have, willingly or unwillingly, accepted this Authority's intervention in this matter and, have also accepted the need to have the same rate both ways on considerations of equity. But, because of local peculiarities caused by varying financial features, they have not been able to come an agreement about a common rate. In recognition of this ground reality, this Authority is inclined to veer away from its earlier stand and introduce some flexibility in the arrangement to promote effective implementation of its Order.

- (iii). The fictitious position created by addition of penal interest on doubtful debts is also a relevant point for consideration. Levy of penal interest on delayed payment is, however, a well-established commercial practice. Just because some of the debts have gone bad or doubtful, there is no reason to abandon such an established practice.
- (iv). The IPA has proposed to reduce the rate of penal interest to 15% and fix it as the ceiling limit. It is noteworthy that the penal interest rate has recently been reduced from 24% p.a. to 18% p.a. Since a range of penal interest rate is to be prescribed, it may not be

necessary to reduce the penal interest rate already in force which will serve only as a ceiling limit in the revised prescription. It is to be recognised that a port trust will have the flexibility to adopt a penal interest rate within the range and it can be less than 18% p.a.

- (v). Penal interest must be viewed as a punitive measure to enforce a disciplined cash and debt management. It may not be correct to view it only as the opportunity cost of funds blocked. In this backdrop, prescribing a penal interest rate only at 1% above the SBI's PLR, as proposed by the IPA, does not seem to achieve the desired result. It has to be recognised that rarely a borrower can obtain loans at the PLR. Further, if penal interest rate is closer to commercial borrowing rates, then there may be a tendency to view (by the other party to the transaction) the Port Trusts / Users as a depository or lending agencies. That being so, this Authority finds it reasonable to prescribe penal interest rates within a range between the minimum of 2% above SBI's PLR rate and a maximum of 18% p.a. The Port Trusts can be allowed to choose the rate convenient to their purpose within this range subject to the following understanding:
- (a). The penal interest rate chosen will apply to both the Port Trusts and the port-users equally.
 - (b). The port trusts must exercise their option and choose a rate within the range prescribed. Any change thereafter can only be with this Authority's approval.
 - (c). The arrangement relating to introduction of a range itself will be reviewed after two years to examine whether a common rate for all the Port Trusts can be prescribed.
- (vi). The IPA has also proposed that the time limit to count delay in refund be enhanced to 30 days from the date of completion of 30 days of service. This Authority has already allowed a time limit of 20 days for processing of such refund claims. The time limit already allowed is liberal; any further increase in the lead-time is not necessary. It is also relevant that the IPA's proposal is to consider the lead-time from the date of completion of services. For a port to process the refund claims the completion of services is not as crucial as production of all required documents by the users. In this context only, this Authority has already prescribed that the delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all documents required from the users whichever is later.
- (vii). The JNPT has suggested allowing 10 days grace period from the date of invoice for the port users to make payment. This Authority has already allowed such a grace period vide its Order dated 3 August 2001.
- (viii). In this context, it will be relevant here to mention that the Calcutta Port Trust (CPT) and Chennai Port Trust (CHPT) (repeatedly) raised doubts about the competence of this Authority to prescribe a penal interest rate for delayed payment / refund. This issue has already been settled by this Authority through its Order dated 19 July 2000 in respect of the CPT and repeated in the case of the CHPT. In the Order related to the CPT, the following position was clearly brought out:
- (a). The prescription of penal interest made by this Authority did not contravene any of the provisions of the MPT Act.
 - (b). An Authority empowered to prescribe rates and associated conditionalities can prescribe penal rates also.
 - (c). If the penal interest levied by the CPT (as per its Scale of Rates even before this Authority passed the common adoption Order) was tenable, then the Order passed by this Authority to extend the principle to refunds to be made by the Port was also justifiable.

367461/2001-3

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides the following: .

- (i). In partial amendment of its earlier Orders on this subject, the rate of penal interest will be in the range between a minimum of 2% above the Prime Lending Rate of the State Bank of India and a maximum of 18% within which the Port Trusts can choose the rate convenient to their purpose.
- (ii). The penal interest rate chosen will apply to both the Port Trusts and the port-users equally.
- (iii). The port trusts must exercise their option immediately and choose a rate within the range prescribed. Any change thereafter can only be with this Authority's approval.
- (iv). The arrangement relating to introduction of a range itself will be reviewed after two years to examine whether a common rate for all the Port Trusts can be prescribed.

8.2. All the major port trusts are directed to amend their respective Scale of Rates to include the revised rate of penal interest (to be) chosen by them.

8.3. This Order will come into effect on expiry of 15 days from the date of its notification in the Gazette of India.

S. SATHYAM, Chairman
[ADVT/III/IV/143/2001/Exty.]